द हिल कल्टिवेटर

वर्ष-1, अंक-9 : जून 2025

जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका

THE HILL CULTIVATOR

MONTHLY E-PAPER OF HPCDP (PHASE-II), JICA-ODA

हिमाचल प्रदेश सरकार आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी : मुख्यमंत्री

*प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी: *मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय बहु-हितधारक सम्मेलन की अध्यक्षता की*

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से आलू प्रसंस्करण संयत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों की आर्थिकी को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क द्वारा 12 जून को शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्ष अनेक नवीन योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि असंतुलित भोजन से लोगों में पोषण संबंधी समस्याओं में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उत्तरी-पूर्वी राज्यों के बाद हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामलों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। खान-पान की आदतों में बदलाव भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 14 प्रतिशत योगदान है। वर्तमान में मौसम में जिस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है, वह कृषि के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। सरकार आने वाले समय में प्राकृतिक खेती उत्पादों के समर्थन मूल्य में और बढ़ोतरी करेगी तथा यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। श्री सुक्खू ने कहा कि जलवायु सहनशील कृषि, दालें और व्यापक पशुपालन एवं चरवाहों को बढ़ावा, पारंपरिक बीज प्रणाली का अधिक उपयोग, जल सुरक्षा और मृदा संरक्षण पर बल आदि ऐसे कदम हैं जिनके माध्यम से हम इन चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकते हैं। ऐसे पारंपरिक बीज और फसलें हैं जो कि प्राकृतिक खेती से उगती हैं, पोषण से भरपूर होती हैं तथा पानी की आवश्यकता भी कम रखती है। हमें ऐसी पारंपरिक फसलों को पुनः इस्तेमाल में लाना होगा। इनमें शोध के माध्यम से और सुधार लाना होगा ताकि हम भावी पीढ़ी को पौष्टिक आहार व स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्राकृतिक खेती के अनुभवों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती से जुड़े प्रदेश के किसानों की सराहना करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। पदमश्री नेक राम शर्मा ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जल, जंगल, जमीन को बचाने सहित मोटे अनाज के महत्व पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, पदमश्री हरिमन, कृषि विशेषज्ञ डॉ. सभ्यसाची दास, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न हितधारक, कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कृषि निदेशालय का दौरा किया

सचिव (कृषि-बागवानी) डॉ. पॉलरासु भी बैठक में शामिल हुए

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने 20 जून को शिमला स्थित कृषि निदेशालय का दौरा किया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभागाध्यक्ष के पद पर फार्म टेक्नोक्रेट को बहाल करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी यह पद टेक्नोक्रेट के पास ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के सचिव (कृषि एवं बागवानी) डॉ. सी. पॉलरासु, कृषि निदेशक डॉ. जीत सिंह ठाकुर, अतिरिक्त कृषि निदेशक डॉ. रविंदर जसरोटिया और हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने कृषि मंत्री का स्वागत किया। कृषि निदेशक ने कर्मचारियों की ओर से मंत्री को राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने का आश्वासन दिया। जायका कृषि परियोजना के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने भी कृषि मंत्री को एक योजना की प्रगति पर एक दस्तावेज सौंपा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना राज्य सरकार का ध्येय : मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के ध्येय से कार्य कर रही है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए अनेक अभिनव पहल की हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा हिमाचल प्रदेश पशु एवं कृषि सखी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 जून को शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट कर, अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति के उत्पादों को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। प्रदेश के हिम ईरा व अन्य उत्पाद दूसरे प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स 'हिम-ईरा' वेबसाइट शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के एक लाख 58 हजार से अधिक किसानों को प्रमाणित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिकिलो किया है, जिससे हमारे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार प्राकृतिक हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदने जा रही है, जिसे हिमाचली हल्दी के नाम से बढ़ावा दिया जाएगा।

भट्टू व करसोग फार्मों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी से बेहतर पॉली-हाउस बनेंगे

हमीरपुर। जायका कृषि परियोजना-2 और एमकेवी एडवांस्ड लि. के अधिकारियों के बीच तकनीकी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान के अवसरों का पता लगाने के लिए परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान की अध्यक्षता में 10 जून को एक बैठक आयोजित की गई। डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि जायका कृषि परियोजना-2 और एमकेवी एडवांस्ड लि. आपसी सहयोग से कृषि फार्मों का विकास होगा। बैठक की शुरुआत एमकेवी के अतिथि प्रतिनिधियों के गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई, जिनमें श्री अकीरा मकिमुरा, श्री काट्सुहिरो फुजिवारा, सुश्री माई हट्टा और श्री मित्सुरु यागुरा शामिल थे। डॉ. राजेश, उप परियोजना निदेशक (एमपीएच) ने भी अपना अभिवादन व्यक्त किया, और भविष्य के सहयोग को मजबूत करने में बैठक के महत्व पर बल दिया। वरिष्ठ विपणन अधिकारी सुश्री नितिका सोनी, ने परियोजना-2 के समग्र उद्देश्यों और प्रमुख घटकों को रेखांकित करते हुए एक व्यापक प्रस्तुति दी और फार्मों पर की जा रही प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एमकेवी एडवांस्ड लि. उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता वाली जापानी फर्म है इनके साथ सहयोग के लिए शुरुआत में दो मॉडल फार्मों की पहचान की गई। ये फार्म हैं जिला कांगड़ा में भट्टू का सब्जी गुणन फार्म (वीएमएफ) और जिला मंडी में करसोग बीज गुणन फार्म शामिल हैं। भट्टू फार्म में 416 वर्ग मीटर और 252 वर्ग मीटर के दो पॉली-हाउस हैं, और करसोग फार्म में 252 वर्ग मीटर के पॉली-हाउस हैं। एमकेवी एडवांस्ड लि. के प्रतिनिधिमंडल ने इन चयनित पॉली-हाउस को तकनीकी सहायता देने में रुचि व्यक्त की, जिसमें उनके समग्र प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेहतर पॉली-हाउस शीट या उच्च प्रदर्शन वाली टिकाऊ और स्पष्ट फिल्म की शुरूआत शामिल है। यह भी चर्चा की गई कि उनकी पॉली-फिल्मों के बेहतर प्रकाश संप्रेषण गुण प्राकृतिक प्रकाश और यूवी किरणों की पर्याप्त मात्रा की अनुमति देकर उच्च गुणवत्ता वाली फसलों की खेती में मदद करते हैं हालांकि, वे 150 माइक्रोन पॉली-मोटी शीट का वितरण करते हैं, जो भारतीय बाजार में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक 200-माइक्रोन फिल्मों की तुलना में बेहतर मानी जाती हैं।

इसके बाद, भट्टू में सब्जी गुणन फार्म (वीएमएफ) का एक फील्ड दौरा किया, जहां जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम), पालमपुर और एचपीसीडीपी के फील्ड स्टाफ ने एमकेवी एडवांस्ड लि. के प्रतिनिधिमंडल टीम का स्वागत किया।

दौरे के दौरान, एमकेवी प्रतिनिधिमंडल ने फील्ड अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के साथ बातचीत की और मौजूदा पॉली-हाउस बुनियादी ढांचे और चल रही गतिविधियों की बारीकी से समीक्षा की।

जायका कृषि परियोजना बीज-हल्दी को बढ़ाएगी : डॉ. पॉलरासु

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (कृषि एवं बागवानी) डॉ. सी. पॉलरासु ने जायका कृषि परियोजना अधिकारियों को राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली हल्दी के बीज को बढ़ाने पर काम जारी रखने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ 18 जून को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. पॉलरासु ने कहा कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आतमा) के परियोजना निदेशक जिले में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जबकि उप कृषि निदेशक प्राकृतिक खेती परियोजना के काम की देख-रेख करेंगे।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आतमा की टीमें सभी 3615 पंचायतों में जाएं और कम से कम 10 प्राकृतिक खेती उत्पादकों को पंजीकृत करें, जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का, गेहूं और हल्दी में से एक का योगदान दे सकें। इस तरह एक लाख प्राकृतिक किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पूरा होगा। यह लक्ष्य मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया है, जिसे तीन सीजन में हासिल किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2, जायका - ओडीए, के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि इस वर्ष परियोजना के द्वारा लगभग 31 टन हल्दी का बीज किसानों और दूसरी संस्थाओं से खरीदा है जिसमें से 29 टन हल्दी के बीज किसानों के लगभग 18 हेक्टर भूमि पर 740 के करीब हल्दी के प्रदर्शन प्लॉट लगवाए हैं। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए 2.97 टन का उपयोग किया गया।

बैठक के दौरान परियोजना निदेशक के साथ राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट का तकनीकी स्टाफ भी मौजूद थे, जबकि सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के जिला परियोजना प्रबंधक भी सचिव (कृषि-बागवानी) से दिशा-निर्देशों को क्षेत्र में ले जाने के लिए ऑनलाइन मौजूद थे।

इस समीक्षा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि निदेशक डॉ. जीत सिंह ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

जायका कृषि परियोजना ने प्रारंभिक देरी की कमी को पूरा किया

100 सिंचाई परियोजनाओं को केवीए को सौंपने के लिए परियोजना तैयार; मार्च 2026 तक 100 और परियोजनाएं पूरी होंगी

हमीरपुर, 19 जून। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना-2, जायका-ओडीए के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से परियोजना के पूरा होने से पहले वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए परियोजना गतिविधियों के त्वरित रणनीतिक कार्यान्वयन के माध्यम से कमी को पूरा करने पर जोर दिया। मंगलवार और बुधवार को यहां हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठकों की अध्यक्षता करते हुए डॉ. सुनील चौहान ने परियोजना को प्रोत्साहित करने वाले समर्थन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, माननीय कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और माननीय सचिव (कृषि-बागवानी) डॉ. सी. पॉलरासु का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन ने परियोजना के हितधारकों को विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में प्रारंभिक देरी की कमी को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन दिया है, इसके अलावा परियोजना कर्मचारियों को किसानों को लाभ पहुंचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभिनव गतिविधियों पर काम करने के लिए प्रेरित किया है। डॉ. चौहान ने बताया कि परियोजना ने पहले ही 100 सिंचाई बुनियादी ढांचे को पूरा कर लिया है और उन्हें आगे के संचालन और रख-रखाव के लिए संबंधित केवीए को सौंपने की प्रक्रिया में है। जबकि फसल विविधीकरण की गतिविधियां पूरी तरह से शुरू हो गई हैं। अगले साल मार्च के अंत तक 100 से अधिक पूरे हो जाएंगे, जहां किसानों का क्षमता विकास शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 12 जिलों में 306 सिंचाई योजनाएं हैं, जो लगभग 30 हजार कृषक परिवारों और 8,500 हेक्टेयर खेती वाले क्षेत्र को कवर करती हैं। प्रदीप शर्मा, उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार, डॉ. करतार सिंह डोगरा व डॉ. संतोष कुमारी, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के विषय विशेषज्ञ डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. राकेश व परियोजना के सह-टीम लीडर अनिल अग्रवाल भी बैठकों में उपस्थित थे। बैठकें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर व सोलन के जिला परियोजना प्रबंधन इकाई क्षेत्रों और 15 खंड परियोजना प्रबंधन इकाई क्षेत्रों में प्रगति और परिणामों की समीक्षा पर केंद्रित थीं। परियोजना निदेशक ने क्षेत्र पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री के बजट आश्वासनों को अक्षरशः लागू करने और माननीय कृषि मंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की प्रतिबद्धता को भी लागू करने के निर्देश दिए। डॉ. सुनील चौहान ने आगे बताया कि परियोजना को उपयुक्त कृषि-व्यवसाय नेटवर्क और फसल विविधीकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर विपणन चैनलों और खरीदारों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि खरीदारों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भोजन एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना ने पहले हाथ के बाजार के रूप में 30 हजार कृषक परिवारों को कवर किया है, जिसके लिए घरेलू पोषण रसोई उद्यानों को बढ़ावा देने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। उपयुक्त कृषक परिवारों को बहुविध सब्जी उत्पादन करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, ताकि वे या तो खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से या स्वयं के खुदरा दुकानों के माध्यम से गांवों के आसपास खुदरा बिक्री करके या किसान समूहों और खरीददार समूहों के बीच उचित तालमेल बनाने के बाद विभिन्न बस्तियों के दरवाजे तक डिलीवरी के लिए पहुंच बनाकर विपणन कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्नत और नवोन्मेषी किसानों की पहचान की गई है, जो थोक में व्यावसायिक खेती करने के इच्छुक हैं, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीतिक और प्रमुख फसलों का उत्पादन, संग्रह और विपणन कर सकें। उन्होंने बताया कि इस समूह को कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए सक्षम बनाया जाएगा और विभिन्न कृषि-व्यवसाय ऑपरेटरों के साथ उचित संबंध स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जेआईसीए कृषि परियोजना के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने फील्ड स्टाफ को सभी 15 ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाइयों में से प्रत्येक में दो मॉडल उप-परियोजना क्षेत्रों का चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मॉडल उप-परियोजना क्षेत्र को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि सभी फसल विविधीकरण और विपणन गतिविधियों को गहनता से कार्यान्वित किया जा सके। इसके अलावा, इन 30 मॉडल उप-परियोजनाओं में फसल-कीट नियंत्रण और निगरानी के लिए ड्रोन की सुविधा होगी, जिसका संचालन परियोजना की महिला सामुदायिक प्रेरकों द्वारा किया जाएगा। परियोजना प्रत्येक मॉडल उप-क्षेत्र के किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मृदा परीक्षण सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन फसल और मौसम पूर्वानुमान की सुविधा भी प्रदान करेगी।

''फसल विविधीकरण से कृषि उपज को बढ़ाना है, कृषि के क्षेत्र में प्रदेश का नाम और ऊंचा उठाना है''

जापानी टीम ने जायका कृषि परियोजना-1 का मूल्यांकन किया

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-1 के कार्यान्वयन के उपरांत मूल्यांकन के तहत जापान से दो सदस्यीय टीम ने 3 और 4 जून 2025 को जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर का दौरा किया। जापानी टीम में श्री मोसिदा तोमो और सुश्री काओरी ओसोन शामिल थे। जायका कृषि परियोजना का प्रथम चरण जुलाई 2021 में पूरा हो गया था। इस मूल्यांकन के दौरान टीम ने परियोजना प्रबंधन इकाई के अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की और परियोजना कार्यान्वयन से जुड़े अनुभव, परिणाम एवं चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पालमपुर इकाई द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। टीम ने ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई देहरा के अंतर्गत धुगियारी प्रवाह सिंचाई योजना तथा धर्मशाला इकाई के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत निर्मित संपत्तियों की भौतिक स्थिति, उपयोगिता और स्थायित्व का अवलोकन किया।

इसके अतिरिक्त, टीम ने लाभार्थी किसानों, किसान विकास संघ (केवीए) सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तथा संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और परियोजना से हुए सामाजिक व आर्थिक लाभों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक पालमपुर, विषय विशेषज्ञ, देहरा इकाई के परियोजना अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और टीम को परियोजना के विभिन्न आयामों की जानकारी प्रदान की। जायका द्वारा समर्थित इस परियोजना के तहत सिंचाई, कृषि विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए टीम ने कहा कि प्रथम चरण ने क्षेत्र में स्थायी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

लैंगिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर प्रशिक्षण दिया

पालमपुर, 27 जून। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-2) के तहत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू), पालमपुर में लैंगिक हिंसा और जेंडर मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत श्री रजनीश शर्मा, विषय विशेषज्ञ, डीपीएमयू पालमपुर द्वारा प्रतिभागियों के स्वागत के साथ हुई। प्रशिक्षण में डीपीएमयू पालमपुर के लगभग 40 प्रतिभागियों ने भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से भाग लिया। इस प्रशिक्षण का नेतृत्व डॉ. बशुबी शील, जेंडर विशेषज्ञ द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण में लैंगिक हिंसा की गंभीरता और सामाजिक, पारिवारिक व कार्यस्थल स्तर पर इसके प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को यह समझाया कि किस प्रकार से परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान लैंगिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने चर्चाओं में भाग लिया और अपने वास्तविक जीवन के अनुभव साझा किए। इस प्रकार की सहभागिता ने विषय को और अधिक प्रभावशाली व समझने योग्य बना दिया। प्रतिभागियों को लैंगिक हिंसा की रोकथाम के उपायों की जानकारी भी दी गई, तथा समुदाय स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उनके व्यक्तिगत दायित्व पर भी बल दिया गया। डॉ. बशुबी ने जेंडर मॉनिटरिंग रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रपत्रों की जानकारी भी दी और प्रतिभागियों को निर्देशित किया कि वे इन रिपोर्टों को अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टों में सम्मिलित करें। इस प्रशिक्षण सत्र ने प्रतिभागियों को लैंगिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया तथा उन्हें परियोजना गतिविधियों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

सिंचाई योजना रानी गाँव बुधों कूहल किसानों को समर्पित

46 किसान परिवारों की 11.86 हेक्टर कृषि भूमि होंगी सिंचित

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-2) के अंतर्गत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कांगड़ा की 8 उप-परियोजनाओं से आए कुल 26 किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषक विकास संघों (केवीए) के महत्व, उनकी भूमिका और भविष्य में परियोजना के प्रबंधन की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। परियोजना के पूरा होने के उपरांत इन संघों को ही परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के संचालन, रख-रखाव और आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। श्री रजनीश शर्मा, विषय विशेषज्ञ, पालमपुर ने किसानों को परियोजना की प्रमुख गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने शेप (लघु कृषक बागवानी सशक्तिकरण संवर्धन), उत्पादन प्रबंधन एवं मूल्य प्राप्ति कार्यक्रम और जायका सब्जी उद्यानों की अवधारणा पर भी चर्चा की, जिनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है। डॉ. प्रेम लाल शर्मा, सेवानिवृत्त जिला परियोजना प्रबंधक ने प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर व्यापक प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना के निर्माण पश्चात उसके सभी संसाधन किसानों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, और संघों को ही उसकी निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने किसानों को नियमित मासिक अंशदान एकत्र करने की भी सलाह दी ताकि रखरखाव एवं संचालन में आर्थिक बाधाएँ न आएं। डॉ. पुरुषोत्तम लाल शर्मा, पीएमसी एक्सपर्ट ने अपने व्यावसायिक अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि परियोजना का मूल उद्देश्य सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के लाभ बताए और बताया कि कैसे वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. योगिंदर पाल ने कहा कि यह परियोजना राज्य के किसानों के लिए आजीविका सुधार का एक सशक्त माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि कृषक विकास संघों की भूमिका परियोजना की दीर्घ कालिक सफलता के लिए अत्यंत निर्णायक होगी।

जायका कृषि परियोजना-2 के कृषक विकास संघों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-2) के अंतर्गत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कांगड़ा की 8 उप-परियोजनाओं से आए कुल 26 किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषक विकास संघों (केवीए) के महत्व, उनकी भूमिका और भविष्य में परियोजना के प्रबंधन की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। परियोजना के पूरा होने के उपरांत इन संघों को ही परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के संचालन, रख-रखाव और आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। श्री रजनीश शर्मा, विषय विशेषज्ञ, पालमपुर ने किसानों को परियोजना की प्रमुख गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने शेप (लघु कृषक बागवानी सशक्तिकरण संवर्धन), उत्पादन प्रबंधन एवं मूल्य प्राप्ति कार्यक्रम और जायका सब्जी उद्यानों की अवधारणा पर भी चर्चा की, जिनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है। डॉ. प्रेम लाल शर्मा, सेवानिवृत्त जिला परियोजना प्रबंधक ने प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर व्यापक प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना के निर्माण पश्चात उसके सभी संसाधन किसानों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, और संघों को ही उसकी निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने किसानों को नियमित मासिक अंशदान एकत्र करने की भी सलाह दी ताकि रखरखाव एवं संचालन में आर्थिक बाधाएँ न आएं।

डॉ. पुरषोत्तम लाल शर्मा, पीएमसी एक्सपर्ट ने अपने व्यावसायिक अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि परियोजना का मूल उद्देश्य सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के लाभ बताए और बताया कि कैसे वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. योगिंदर पाल ने कहा कि यह परियोजना राज्य के किसानों के लिए आजीविका सुधार का एक सशक्त माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि कृषक विकास संघों की भूमिका परियोजना की दीर्घ कालिक सफलता के लिए अत्यंत निर्णायक होगी।

जायका कृषि परियोजना-2 की बहाव सिंचाई उप परियोजना केवीए समखेतर को सौंपी

70 किसान परिवारों की 12.80 हैक्टर भूमि होगी सिंचित

जोगिंदरनगर, 20 जून। जोगिन्दरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत बुल्हा भड़याड़ा के अंतर्गत गांव समखेतर में खंड परियोजना प्रबंधन इकाई सरकाघाट द्वारा बहाव सिंचाई उपपरियोजना भेड़ा नाला से समखेतर को कृषक विकास संघ (केवीए) समखेतर को सौंपा गया। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परियोजना प्रबंधक हेमराज वर्मा ने की। इस कार्यक्रम के दौरान जायका अधिकारियों ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी साझा की तथा उपस्थित ग्रामीणों से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला परियोजना प्रबंधक हेमराज वर्मा ने जानकारी दी कि इस बहाव सिंचाई उपपरियोजना के निर्माण पर लगभग 40 लाख लगभग 70 लाभार्थी किसान परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गांव में सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस परियोजना से स्थानीय किसानों को वर्ष भर पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस सिंचाई सुविधा का उपयोग कर सब्जियों एवं अन्य नकदी फसलों की खेती करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस दौरान केवीए, समखेतर के प्रधान व सदस्यों ने परियोजना के अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस परियोजना से गांव में लोग दोबारा बंजर भूमि में खेती करने के काबिल हुए हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया की हम सब अब सब्जियों एवं अन्य नकदी फसलों की खेती करेंगे जिससे हमारी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। इस कार्यक्रम में खंड परियोजना प्रबंधक अश्वनी कुमार, केवीए समखेतर के प्रधान जगदीश चंद, कृषि विशेषज्ञ चौंतड़ा ऋचा बामण सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जायका परियोजना द्वारा बनाई चार सिंचाई उप-परियोजनाएं किसानों को सौंपी

कांगड़ा जिला में 275 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, 1107 किसान परिवार होंगे लाभान्वित

हिमाचल प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-द्वितीय के अंतर्गत कांगड़ा जिला में 4 बहाव सिंचाई उप-परियोजनाओं को किसानों सौंपा। इन परियोजनाओं से न केवल क्षेत्र की कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, बल्कि किसानों की आय और उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

परियोजना प्रबंधन इकाई, देहरा द्वारा इन उप-परियोजनाओं को 4.33 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। कुल 275 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने से 1107 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इससे न केवल सिंचाई पर निर्भरता बढ़ेगी, बल्कि वर्षा पर आधारित खेती की अनिश्चितता भी काफी हद तक कम होगी। इस अवसर पर जिला प्रबंधन इकाई से डॉ. रजनीश कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. विवेक कंवर, कृषि विशेषज्ञों, स्थानीय किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चारों बहाव सिंचाई उप-परियोजनाओं को कृषक विकास संघों को समर्पित किया, कार्यक्रम के दौरान इन योजनाओं की महत्ता, प्रभाव और किसानों के जीवन में आने वाले संभावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

परियोजनाओं का विस्तृत विवरण एवं उनके संभावित लाभ:

1. मालती कूहल (ग्राम पंचायत नंदेहड़)
लागत: 80.91 लाख
सिंचित भूमि: 62.17 हेक्टेयर
लाभार्थी किसान: 335

इस कूहल से आसपास के खेतों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे सब्जी उत्पादन और नकदी फसलों में वृद्धि होगी।

2. दवाड़ कूहल (ग्राम पंचायत दवाड़)
लागत: 1.26 करोड़
सिंचित भूमि: 71.78 हेक्टेयर
लाभार्थी किसान: 190
क्षेत्र की प्रमुख कूहलों में शामिल इस योजना से बड़े क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी और परंपरागत जल स्त्रोतों का संरक्षण भी होगा।

3. नागनी कूहल (ग्राम पंचायत कुहाला)
लागत: 1.01 करोड़
सिंचित भूमि: 38.92 हेक्टेयर
लाभार्थी किसान: 195
यह योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी, जो अब तक वर्षा पर निर्भर थे।

4. पुलेहाली कूहल (ग्राम पंचायत कछियारी)
लागत: 1.24 करोड़
सिंचित भूमि: 102.22 हेक्टेयर
लाभार्थी किसान: 387
यह उप-परियोजना क्षेत्र की सबसे बड़ी बहाव सिंचाई प्रणाली बनकर उभरी है, जिससे कई गांवों को फायदा मिलेगा।

किसानों की आय में वृद्धि और जल प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा

इन बहाव सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल स्त्रोतों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने की दिशा में प्रेरणा मिलेगी। परियोजना के माध्यम से जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, फलों की बागवानी और नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है,

जिससे किसानों की लागत में कमी और लाभ में वृद्धि होगी

इस अवसर पर डॉ. रजनीश कुमार ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना नहीं है,

बल्कि किसानों को संगठित कर उन्हें बाजार, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं कृषि उद्यमिता की ओर अग्रसर करना भी है।

उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और कृषि को व्यवसायिक रूप में विकसित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं।

सिरमौर के जोक किसानों ने दिल्ली भेजी सब्जियां

नाहन। हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना के अधिकारियों ने 20 जून को किसानों से टमाटर, शिमला मिर्च और बीन्स सहित सब्जियों का संग्रह करके उनके व्यापार की सुविधा सिरमौर के जोक सेराजौली पनेवाटा में उप-परियोजना में शुरुआत की। जायका कृषि परियोजना के अधिकारियों ने उपजी सब्जियों को एकत्रित उपज को किया और दिल्ली के नागलोई बाजार में भेजने के लिए तैयार किया। शुक्रवार को कुल दो टन टमाटर, 3.5 क्विंटल शिमला मिर्च और छह क्विंटल बीन्स भेजे गए। समन्वय किया। उपज ले जाने वाले वाहन को सफलतापूर्वक लोड किया गया और उसी दिन बाजार में भेज दिया गया,

जिसका उद्देश्य बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना था और साथ ही राज्य जायका कृषि परियोजना की जिला प्रबंधन इकाई सोलन के तहत ब्लॉक प्रबंधन इकाई नाहन में आने वाली उप-परियोजना जोक से राजौली पनेवाटा उप-परियोजना में शामिल किसानों के लिए प्रभावी बाजार संपर्क स्थापित करना था।

जायका और सरकार का कृषि व ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण

कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका) का दृष्टिकोण सतत खाद्य उत्पादन और आपूर्ति, गरीबी उन्मूलन और गतिशील ग्रामीण समुदायों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वे उत्पादन, वितरण और बिक्री को ध्यान में रखते हुए, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण के माध्यम से आजीविका में सुधार पर जोर देते हैं। जायका जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने को भी प्राथमिकता देता है।

जायका के दृष्टिकोण के प्रमुख पहलुओं में खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तन लचीलापन, सामुदायिक सशक्तिकरण, सतत उपयोग, सहयोग और साझेदारी एवं शेप दृष्टिकोण शामिल हैं । हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना-2 जायका के दृष्टिकोण के प्रमुख पहलुओं को अक्षरशः लागू कर रही है और राज्य सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

जायका टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन, सिंचाई में सुधार और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर, राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर स्थिर खाद्य उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

जायका का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, कृषि गतिविधियों के विविधीकरण को

बढ़ावा देकर और कृषि-से-बाहर की गतिविधियों सहित विभिन्न माध्यमों से आय सृजन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना है।

जायका बुनियादी ढाँचे में सुधार, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देकर और संस्थागत क्षमता को मज़बूत करके, उत्पादन से लेकर विपणन और बिक्री तक, संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला का समर्थन करता है।

जायका जल-कुशल सिंचाई, सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों और मौसम सूचकांक बीमा को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने पर केंद्रित है।

जायका सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देकर, सामुदायिक संगठनों को मज़बूत बनाकर और संसाधनों व बाज़ारों तक पहुँच में सुधार करके महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने वाली पहलों का समर्थन करता है।

जायका सतत भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जैव ईंधन ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है जो खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती है, और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाने का समर्थन करता है।

जायका अपनी परियोजनाओं की प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों, सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग पर ज़ोर देता है।

जायका स्थानीय नेताओं और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके और जापान की कृषि विशेषज्ञता को साझा करके मानव संसाधन विकास में निवेश करता है।

जायका शेप दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो किसानों को बाज़ार की ज़रूरतों को समझने और उसके अनुसार अपने उत्पादन को समायोजित करने के लिए प्रोत्साहित करके बाज़ार-उन्मुख उत्पादन पर केंद्रित है।

डॉ. सुनील चौहान
परियोजना निदेशक
एवं प्रधान सम्पादक

सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर होता हिमाचल

महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हमारे गांव समर्थ है तो भारत मजबूत है। महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गांवों और ग्रामीणों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। गांव और गांव से जुड़े लोगों की समस्याओं को जानने के लिए मुख्यमंत्री ने उनके साथ सीधा संवाद कायम किया है। मुख्यमंत्री प्रशासन को गांव के द्वार ले गए हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ग्रामीण लोगों के साथ रहकर उनके दुख दर्द को जान रहे हैं।

गांवों के लोगों के लिए यह कल्पना से परे था कि प्रदेश का मुखिया उनके घर में आकर रात्रि ठहराव कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों के साथ मुख्यमंत्री उन्ही के रंग में रंग जाते हैं। उनकी मनोदशा और संघर्ष को जानकर मुख्यमंत्री गांवों के उत्थान की दिशा में कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। डोडरा क्वार, कुपवी के टिक्कर गांव, कुल्लू के शरची में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को जाना। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ रात्रि ठहराव कर मुख्यमंत्री यह रेखांकित कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों को सरकार प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

अपनी शालीनता और सरलता से मुख्यमंत्री ग्रामीण लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ रहे हैं। ग्रामीण लोगों के साथ उन्ही के परिवेश में रहकर मुख्यमंत्री गांव के लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए नीतियों और योजनाओं को साकार रूप दे रहे हैं। जन सेवा को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री ने दुर्गम पांगी घाटी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन करवा कर यह संदेश दिया कि हिमाचल की इस विकास यात्रा में हर हिमाचलवासी सहभागी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के बजट में ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर योजनाएं लाई गई।

सुखी ग्राम-खुशहाल किसान को ध्येय मानकर मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम किया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने यह नीतिगत निर्णय लिया है। सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान करना है। वर्तमान में प्रदेश में 1.98 लाख किसान और बागवान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन किसानों को लाभान्वित करते हुए 1500 से अधिक किसानों से प्राकृतिक पद्धति से तैयार 400 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है।

प्राकृतिक खेती से तैयार खाद्यान्नों को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार ने बाजार में हिमभोग-हिम मक्की आटे के

ब्रॉन्ड को लॉन्च किया है। पांगी को पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री की यह भी परिकल्पना है कि हिमाचल देश में केवल दूध उत्पादन तक सीमित न रहे बल्कि हिमाचल डेयरी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हिमाचल दूध पर एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य है। गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रतिलीटर किया गया है। पशुपालकों को 2 रुपये प्रतिलीटर परिवहन सब्सिडी भी दी जा रही है। डेयरी क्षेत्र को संबल प्रदान करते हुए हिमगंगा योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दतनगर में 50 हजार प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लाट से 20 हजार दूध उत्पादकों को लाभ मिल रहा है। जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ऑटोमेटिक दूध प्रसंस्करण और दूध उत्पाद प्रसंस्करण प्लाट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुल्लू, नाहन, नालागढ़, ऊना और हमीरपुर में 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मॉडल टैक्नोलॉजी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लाट स्थापित किए जाएंगे।

हिमाचल की पहचान सेब राज्य से फल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को विस्तार प्रदान कर रहे हैं।

प्रदेश में 1292 करोड़ रुपये की एचपी शिवा परियोजना के तहत बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के 28 विकास खंडों में 6 हजार हैक्टेयर को बागवानी के तहत लाने के दृष्टिगत विविध कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 37.60 हजार मीट्रिक टन फलों को प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदा है। बागवानों को सीए स्टोर की सुविधा प्रदान की जा रही है। रोहड़ू में 29.22 करोड़ रुपये से निर्मित अत्याधुनिक सीए स्टोर बागवानों को समर्पित किया गया है।

टैक्नोलॉजी के युग में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के उत्पादों के सुरक्षित परिवहन के लिए ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजनाएं तैयार की गई है। ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के मुख्यमंत्री के प्रयासों की झलक अब देखने को मिल रही है। अच्छे दामों पर अपनी मेहनत की फसल को बिकता देख किसानों के चेहरों को खुशी यह बयां कर रही है कि सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार किया जा रहा है।
(साभार: हिमाचल प्रदेश सूचना जनसंचार-फीचर)

किसान जुलाई तक कर सकते हैं धान की रोपाई

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के कृषि विशेषज्ञों ने जुलाई में होने वाले कृषि कार्यों को लेकर सलाह जारी की है, ताकि किसान समय पर खेती कर अच्छी कमाई कर सकें। कृषि विवि के विशेषज्ञों की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि धान की रोपाई कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार जुलाई तक की जा सकती है। रोपाई करते समय पौधों की आपस में दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए एक स्थान पर एक या दो पौधे लगाएं और पांच से 10 दिन बाद जहां पर पौधे खराब हो जाएं, वहां पर दोबारा रोपाई कर दें।

धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 किलोग्राम मैचिटी का 4-5 सेंटीमीटर खड़े पानी में रेत में मिलाकर इसका छिड़काव करें। जो किसान मक्की की

बिजाई जून के प्रथम पखवाड़े में कर चुके हैं, उन खेतों में क्षेत्र के हिसाब से यूरिया डाल दें। जिन खेतों में सब्जियां या अन्य फसल लगी थी उन खेतों में मक्की की बिजाई अभी भी की जा सकती है। दलहनी फसल उड़द की निचले मध्यवर्ती क्षेत्रों में हिम माश-1, यूजी- 218, पंत यू-19 एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में पालमपुर-93 किस्म लगाई जा सकती है। मूंग की लाइनिंग मूंग नंबर-1, सुकेती-1, एसएमएल- 668 और कुल्थी की एचपीके-4, बैजू या

बीएलजी-1 किस्म लगाएं। इन फसलों

(साभार: हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर)

की बुवाई केरा विधि द्वारा पंक्तियों की दूरी एक फुट रखते हुए करें।

दलहनी फसलों की बिजाई करते समय इफको मिश्रित खाद 12:32:16 का प्रयोग करें। जहां पर मिश्रित खेती करना हो जैसे मक्का के साथ इन फसलों को लगाना हो वहां पर नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल न करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए दलहनी फसलों में लासो या स्टांप चार से पांच लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 48 घंटे के अंदर अच्छी तरह छिड़काव कर दें। तिलहन फसल सूरजमुखी की किस्म ईसी-68415 की बिजाई एक हेक्टेयर में 10-12 किलोग्राम बीज की दर से की जा सकती है। वहीं, प्रदेश के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में फूलगोभी की अगेती किस्म पालम उपहार, इंप्रूव्ड जैपनीज, पूसा दीपाली, एवं संकर किस्म मेघा एवं बरखा की पनीरी दें। गोभी वर्गीय सब्जी की तैयार पौध को 45 सेंटीमीटर पौधे एवं पंक्ति की दूरी रखते हुए रोपाई करें। इस समय टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च एवं लाल मिर्च और अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों में नाइट्रोजन डाल कर निराई गुड़ाई करते समय डाल दें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की पालम समूल, पंजाब 89, लिंकन, आजाद मटर-1, पालम प्रिया की बिजाई करें।

''फसल विविधीकरण से कृषि उपज को बढ़ाना है, कृषि के क्षेत्र में प्रदेश का नाम और ऊंचा उठाना है''

जायका कृषि परियोजना में कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करें: डॉ. सुनील चौहान

हमीरपुर। परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना में कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करके वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, उन्होंने प्रभागाध्यक्षों द्वारा फीडबैक प्रारूपों में संशोधन करके प्रभावी निगरानी पर भी बल दिया है। डॉ. चौहान 24 जून को हमीरपुर में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) की आंतरिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। चर्चा के दौरान, हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2, जायका-ओडीए के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस बैठक में राजेश कुमार-उप परियोजना निदेशक (डीपीडी-एमपीएच), करतार सिंह-उप परियोनजना निदेशक (डीपीडी-एसडब्ल्यूसी), संतोष कुमारी-उप परियोजना निदेशक (डीपीडी-एएंडई), आशीष आनंद-एसएमएस (कृषि), राकेश शर्मा एसएमएस (कृषि), अनु यादव-एसएमएस (कृषि), नितिका सोनी, वरिष्ठ वित्तपन अधिकारी, ज्योति ठाकुर-कृषि विशेषज्ञ, प्रियंका शर्मा-एईओ और जगपाल-एमआईएस / जीआईएस तकनीशियन और पीएमसी की ओर से अनिल अग्रवाल- सह-टीम लीडर, डॉ. पीएल शर्मा-कृषि विज्ञानी, सुदर्शन सूर्यवंशी-एफपीओ विशेषज्ञ और सुशील शर्मा-आईईसी विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित थे।

डॉ. चौहान ने कहा कि हाल ही में आयोजित जो समीक्षा बैठकें 16, 17 और 21 जून को आयोजित की गईं उनकी कार्य सूचि संबंधित प्रभागों द्वारा तैयार करके फील्ड स्तर पर लागू करवाई जाए। प्रस्तुतियों के अपडेट हुए टेम्प्लेट की जानकारी 23 जून को सभी स्तर पर दे दी गई थी।

बैठक में अगस्त की समीक्षा बैठकें जिला प्रबंधन ईकाइयों के स्तर पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। उप-परियोजना निदेशक को इन समीक्षा बैठकों के लिए सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में 20 जुलाई तक प्रस्तुति टेम्प्लेट को अपडेट करने और फील्ड स्टाफ के उन्मुखीकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत करने से पहले डीपीडी द्वारा अभिलेखों / सूचनाओं का सत्यापन किया जाना जरुरी है।

ये निर्णय भी लिया गया कि संभागीय प्रमुख (डीपीडी) यह सुनिश्चित करेंगे कि उप-परियोजना स्तर पर आयोजित प्रसंस्करण उद्योग के लिए संबंधित दस्तावेजों को अंतिम रूप देना; और हल्दी के स्थानीय पहचान पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करना।

इस बैठक में परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने प्रभागवार प्रमुख मुद्दे उठाये जिनमें अगली बैठक तक अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यों लागू करने के लिए कहा गया।

राज्य सिंचाई विभाग के लिए कार्य:

क) पीएमसी के सीओटीएल द्वारा एफआईएस पुलेवाली कुहल (बीपीएमयू देहरा) और एफआईएस अपर सेओबाग (बीपीएमयू कुल्लू) का स्थल दौरा सुनिश्चित करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ख) डीपीएमयू स्तर पर भी ई-ऑफिस पर काम करने वाले अधिकारियों की संख्या में तेजी लाना। ग) पीएमयू के आईईसी विंग द्वारा डीपीएमयू स्तर पर नोडल अधिकारियों (आईईसी) से नियमित रूप से सूचना, डेटा और सफलता की कहानियाँ प्राप्त करना सुनिश्चित करना।

एमपीएच प्रभाग के कार्य:

1) पीएमवीआरपी और जायका सब्जी उद्यान से संबंधित कार्यों के साथ निगरानी पत्रक सुनिश्चित करना। साथ ही किचन गार्डन और शेप के माध्यम से फसल विविधीकरण के तहत उपलब्धियों पर सफलता की कहानियां / प्रोमो बनाना। 2) डीपीएमयू स्तरों पर किसान उत्पादक संगठनों के गठन और एफपीओ के गैप प्रमाणीकरण के लिए एजेंसीयों को अंतिम रूप देना। 3) कृषि व्यवसाय विपणन और मूल्य श्रृंखला विकास पर एक दिवसीय एक या दो कार्यशालाएं आयोजित करना। *खेती में कृषि व्यवसाय के विकास में संस्थानों की भूमिका। *आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरण (संस्थागत और प्रक्रियाएं)। *खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। *फसल विविधीकरण उपकरण। *कृषि व्यवसाय से किसानों को जोड़ना। *कृषि निवेशों और उत्पादन के लिए प्रबंधन व्यवस्था *बैंक/नाबार्ड की भागीदारी *वेयरहाउसिंग/प्रसंस्करण/विपणन; *कृषि मशीनरी; *कृषि उपज का निर्यात। *आईसीटी का उपयोग, आदि। 4) एचएफएन से एफपीओ गठन के लिए आशय पत्र में तेजी लाई जाएगी। 5) रक्षा मंत्रालय के वीसीएमडी घटक के तहत एआईएफ और एमआईडीएच जैसी विभिन्न योजनाओं के अभिसरण की संभावना। 6) डीपीएम और बीपीएम से कार्य योजनाएं क) कॉर्पस फंड ख) आजीविका सेवा क्षेत्र ग) कृषि मशीनरी। 7) हल्दी के लिए ट्रेड मार्क,

कृषि विस्तार प्रभाग के कार्य:

1) 7 और 8 जुलाई को समेती, मशोबरा में आयोजित तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण में सभी संबंधित भाग लेंगे। 2) सुनिश्चित करें कि निगरानी पत्रक और किसान कार्ड पर डेटा उन उप-परियोजनाओं के संबंध में रिकॉर्ड पर लिया जाए जहां फसल विविधीकरण योजना लागू की जा रही हैं।

विस्तार एवं प्रशिक्षण गतिविधियों, मूल्य श्रृंखला और बाजार विकास का गतिविधि रजिस्टर संबंधित पीएमयू द्वारा रखा जाए, जिसका संबंधित बीपीएम द्वारा मासिक रूप से सत्यापन किया जाए। इनमें बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के लिए बनाए गए साइट ऑर्डर बुक का सत्यापन भी शामिल है।

इसके अलावा, पीएमसी के सह-टीम लीडर को प्रत्येक माह की 2 और 17 तारीख को या तदनुसार अगले कार्य दिवसों पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया।

इस बैठक में निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन करने का निर्णय लिया गया।

*हिमाचल प्रदेश में सहभागी सिंचाई प्रबंधन, *परियोजना के चरण-2 में उप-परियोजना विकास के सूक्ष्म नियोजन की प्रभावशीलता, *बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैदानी और *मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फसल उत्पादन का नियोजन।

किसानों को करवाया बाजार उन्मुख खेती के लिए खेत भ्रमण व किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन

धर्मशाला। ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई, धर्मशाला के तहत 24 जून को एक विशेष फील्ड विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बड़ूहल कूहल और रिड्डा कूहल क्षेत्रों में आयोजित किया गया, जहां किसानों को बाजार उन्मुख खेती यानी लघु कृषक बागवानी सशक्तिकरण एवं संवर्धन (शेप) की अवधारणा से अवगत कराने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को संगठित करना, बाजार से जोड़ना, फसल योजना की समझ विकसित करना तथा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को बाजार आधारित खेती, फसल विविधीकरण, आधुनिक उत्पादन तकनीकों और आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। इस अभियान में विशेष रूप से महिला किसानों की भागीदारी उल्लेखनीय रही, जिससे यह पहल और भी समावेशी बन गई। स्थानीय महिलाओं ने इस कार्यक्रम को न केवल देखा बल्कि उससे जुड़कर अपनी उत्सुकता और भागीदारी भी दर्शाई। इस अभियान के माध्यम से किसानों में जागरूकता, आत्मविश्वास और स्थानीय बाजारों से जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कार्यक्रम ने किसानों को संगठित होकर कार्य करने और बाजार मांग के अनुसार फसल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया, जो आने वाले समय में उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

इस कार्यक्रम में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक अंकिता शर्मा, कृषि विकास अधिकारी, आकाश, सहायक अभियंता, सुविंका शर्मा और रुचिका डोगरा ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

सिंचाई उप परियोजना कुसमल बगौरा-2 में विस्तार भ्रमण व जागरूकता शिविर का आयोजन किया

पालमपुर। ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई पालमपुर द्वारा फ्लो इरिगेशन स्कीम कुसमल बगौरा-2 में 06 जून को एक विस्तार भ्रमण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक अमित भूषण, सहायक अभियंता विक्रांत राणा तथा सहायक अभियंता स्वाति सूद ने सक्रिय भागीदारी की। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों को परियोजना एवं उससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी देना तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के दौरान किसानों को फ्लो इरिगेशन स्कीम के निर्माण, संचालन व रख-रखाव की प्रक्रिया, किसान विकास संघ (केवीए) की गतिविधियां, किसानों की आय बढ़ाने के उपाय, किसान कार्ड का रख-रखाव, तथा केवीए कार्यवाही पंजिका के सही रिकॉर्ड संधारण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों के साथ संवाद करते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना उन्हें किस प्रकार लाभ पहुंचा सकती है और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बेहतर प्रबंधन कैसे संभव है। किसानों को यह भी समझाया गया कि संगठनात्मक भागीदारी से योजना की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। इस जागरूकता अभियान से किसानों में परियोजना को लेकर जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वे इसकी विभिन्न गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। कार्यक्रम ने किसानों को परियोजना के उद्देश्यों, उनके दायित्वों और लाभों की स्पष्ट समझ प्रदान की।

प्राकृतिक खेती, मोटे अनाजों पर प्रशिक्षण

चम्बा। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, चम्बा द्वारा प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों (मिलेट्स) को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विभिन्न उप-परियोजनाओं में प्रदर्शन प्लॉट और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस आयोजन में ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई, चम्बा के विस्तार अधिकारी राधिका कपूर और साहिल पठानिया सहित अनेक स्थानीय लाभार्थी किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों और मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रेरित करना था ताकि खाद्यान्न उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार हो सके।

प्रशिक्षण सत्रों के दौरान मडुवा (फिंगर मिलेट) जैसे पोषक मोटे अनाजों के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। प्रतिभागियों को इन अनाजों के स्वास्थ्यवर्धक लाभ, जलवायु अनुकूलन क्षमता और सतत कृषि पद्धतियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

एक व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से प्रतिभागियों कोजीवामृत-एक पारंपरिक जैविक उर्वरक-की तैयारी और इसके छिड़काव की विधि सिखाई गई। इसके उपयोग से फसल उत्पादन में होने वाले लाभों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया गया, जिससे किसानों का विश्वास प्राकृतिक खेती के प्रति और अधिक दृढ़ हुआ।

कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को मक्का और मिलेट्स के बीज भी वितरित किए गए, जिससे उनमें प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों को अपनाने के लिए उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ। किसानों ने इस कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।

इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल किसानों को टिकाऊ कृषि की ओर प्रेरित करती हैं, बल्कि पोषण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होती हैं।

कुल मिलाकर, यह पहल प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों के महत्व को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने में सफल रही और क्षेत्र में सतत कृषि विकास की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुई।

ऊना में दो शिविर आयोजित

ऊना। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2, जायका-ओडीए के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधक इकाई, ऊना में दो जागरूकता शिविर अयोजित किये गये।

खंड परियोजना इकाई, ऊना ने उप परियोजना बरनोह ऊना में एक शिविर का आयोजन किया। जागरूकता शिविर में कृषि प्रसार अधिकारी दीप कौर द्वारा सभी किसानों के साथ परियोजना की विस्तृत रूप में चर्चा की गई।

प्रशिक्षण शिविर के दौरान किसानों को किचन गार्डन किट बांटी गई जिसकी मदद से किसानों को अपने घर में जैविक सब्जियां उगाने और जहर मुक्त खेती करने के लिए प्रेरित किया।

कृषक विकास संघ के प्रधान स्वर्ण सिंह व उपस्थित सभी किसानों ने किचन गार्डन किट एवं उससे सम्बंधित जानकारी देने पर जायका परियोजना का आभार व्यक्त किया और साथ ही यह आश्वासन दिया की वो किचन गार्डनिंग करके स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे।

इसी बीच, खंड परियोजना प्रबंधक इकाई ऊना द्वारा उप परियोजना बबेहड़ में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया जिसमें कृषि विशेषज्ञ मनीषा शर्मा द्वारा सभी किसानों को कृषक विकास संघ के उद्देश्य एवं मानदंड विषय पर जानकारी व प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण शिविर के दौरान किसानों को किचन गार्डन किट बांटी गई जिसकी मदद से किसानों को अपने घर में जैविक सब्जियां उगाने और जहर मुक्त खेती करने के लिए प्रेरित किया कृषक विकास संघ के प्रधान श्री तिलक राज व उपस्थित सभी किसानों ने किचन गार्डन किट एवं उससे सम्बंधित जानकारी देने पर जायका परियोजना का आभार व्यक्त किया और साथ ही यह आश्वासन दिया की वो किचन गार्डनिंग करके स्वस्थ जीवनशैली को अपनाएंगे।

सिंचाई उप परियोजना पपाहन की डीपीआर अंतिम रूप देने हेतु तकनीकी निरीक्षण

किसानों की सहभागिता से तैयार हुई समावेशी योजना

पालमपुर। ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई पालमपुर और ब्लॉक परियोजना प्रबंधक ज्वाली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 23 जून को फ्लो इरिगेशन स्कीम पपाहन में एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग निरीक्षण भ्रमण का आयोजन किया गया। इस तकनीकी दौरे में पीएमसी विशेषज्ञ ओपी चौहान तथा ज्वाली इकाई के इंजीनियरिंग स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य एफआईएस पपाहन योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देना था।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकताओं, प्रस्तावित कार्यों की व्यवहार्यता, जल प्रवाह की दिशा, संरचना की मजबूती और किसानों की आवश्यकताओं के आधार पर सभी तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा की गई। यह निरीक्षण किसान विकास संघ के प्रधान और लाभार्थी किसानों की उपस्थिति में परियोजना स्थल पर किया गया, जिससे योजना में सीधे किसानों की राय को शामिल किया जा सके। किसानों के साथ सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों को समझते हुए एक समावेशी और व्यवहारिक योजना तैयार की गई। प्रस्तावित कार्यों में जहाँ-जहाँ बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई, वहां सुधार करते हुए डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया। इस भ्रमण का मुख्य निष्कर्ष यह रहा कि एफआईएस पपाहन योजना की डीपीआर औपचारिक रूप से फाइनल कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सकेगा।

यह दौरा तकनीकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल रहा, जो आगामी समय में क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने और सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम सिद्ध होगा।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका ओडीए) के स्वामित्व में परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
फोन: 01972-223059. ई-मेल : iechpjicaagriculture9@gmail.com, Website: www.hpjicaagriculture.com